होगी और क्या सरकार द्वारा इस मांग को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है ; और

(घ) इस क्षेत्र के बैंकों का क्या योगदान रहा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1981 की जनगणना आंकड़ों के योजन के आधार पर 1,3,2001 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय भवन संगठन द्वारा कुल आवास स्टाक 192.6 मिलियन होने का अनुमान लगाया है जिसमें आवास स्टाक 168.2 मिलियन स्वीकार्य होगा ।

(ख) आवास राज्य का विषय है । आवास की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त योजनाओं को प्रतिपादित करना मुख्यतः राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । राष्ट्रीय आवास नीति में बहुत से उपाय निर्धारित हैं जिनको केंद्र/राज्य तथा नगर पालिका स्तर पर सरकार द्वारा करना होगा जिससे आवास निर्माण की गति में वृद्धि होगी । वे उपाय इस प्रकार हैं :

(i) कानूनी तथा अन्य प्रतिबन्ध हटाना ।

(ii) आवास वित्त के अंतर्वाह में वृद्धि करना ।

(iii) विकसित भूमि की आपूर्ति, मूलभूत सेवाओं, भवन सामग्रियों आदि में वृद्धि करना ।

(iv) केंद्र सरकार के मार्ग दर्शन में राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध कार्य योजनाओं का प्रतिपादन और कार्यान्वयन ।

(ग) सन 2001 तक ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी 25.5 मिलियन एकक अनुमानित है । राज्य क्षेत्र आवास स्कीमों के अतिरिक्त इंदिरा आवास योजना नामक एक केंद्रीय स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त हुए बंधुवा मजदूरों को मुफ्त आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रचालन में है । यह स्कीम कतिपय संशोधनों सहित 8वीं योजना में जारी रहेगी । 1991-92 तक इस स्कीम के अंतर्गत 10.57 लाख मकानों का निर्माण किए जाने की सूचना है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में आवास कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए ये बैंक प्रतिवर्ष अपनी संवृद्धि निक्षेपों का 1.5 प्रतिशत निर्धारित कर रहे हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में धपलेबाजी

1759. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **शहरी विकास** मंत्री 6 सितम्बर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 871 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में गैर-कानूनी नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं/धांधली, षडयंत्र और धपलेबाजी के मामलों की जांच के संबंध में क्या प्रगति हुई है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने के लिए सौंपे गए थे ; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण में गैर-कानूनी नियुक्तियों से संबंधित अपराधों की जांच के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । केंद्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इस संबंध में आगे कार्रवाई की जा सकती है ।

Floating of Irrigation Bond

1760. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to float an Irrigation Bond to raise adequate resources for agricultural during the Eighth Plan period; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) and (b) There is no proposal to float Irrigation Bond to raise adequate resources for agriculture during the Eighth Plan period. However, for expeditious completion of some of the Nationally important irrigation projects in the country, it was contemplated to provide special central assistance to the States during the Eighth Plan period. Due to resource constraints, the planning Commission could not accept the proposal and has suggested that the issue of funding for the National Projects be first discussed with the States as the overall National resource availability for irrigation sector is not going to change thereby.

छोटे किसानों को सिंचाई सुविधायें

1761. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या जल संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटे किसानों को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वृहद तथा मध्यम परियोजनायें एवं लघु सिंचाई स्कीमें अपने कमान क्षेत्रों के अंतर्गत छोटे किसानों सहित सभी किसानों को सिंचाई सुविधायें प्रदान करती है ।

(ख) वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं तथा लघु स्कीमों के जरिए सृजित सिंचाई क्षमता का राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा हजार हेक्टेयर में सृजित सिंचाई क्षमता के लिए लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1989–90	1990–91	1991–92
1.	आंध्र प्रदेश	195.98	200.25	200.00
2.	अरूणाचल प्रदेश . . .	2.50	3.55	4.05
3.	असम	71.42	82.00	80.00
4.	बिहार	389.00	390.00	440.00
5.	गोआ	3.89	2.61	3.50
6.	गुजरात	96.00	51.00	66.00
7.	हरियाणा	40.00	26.10	43.60
8.	हिमाचल प्रदेश . . .	5.20	3.15	3.00
9.	जम्मू व कश्मीर . . .	6.42	5.80	2.93
10.	कर्नाटक	58.24	91.00	85.00
11.	केरल	45.89	52.10	75.85